शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में अनुसूचित जाति की भूमिका का मूल्यांकन

प्राप्तिः 11.05.2022
स्वीकृतः 04.06.2022

44

डॉ० अलका रानी
सहायक अध्यापक
कम्पोजिट विद्यालय, खरखौदा
मेरठ (उ०प्र०)
ईमेलः *rakeshkumarmeerut23@gmail.com*

सारांश

सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आज भी अनुसूचित जाति के समुदाय के लोगों की भूमिका वांछनीय है फिर भी भारतीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था में उन्होंने अपनी भूमिका सुनिश्चित की है। भारतीय संविधान ने जहाँ उनके विकास में बाधक बाधाओं को दूर किया, उसी के माध्यम से उनकी राजनीतिक सहभागिता को एक नये आयाम तक पहुँचाया है, जिसके माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास सम्भव हो सके। सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए डॉ0 अंबेडकर ने अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की थी। पिछले चार दशकों में अनुसूचित जातियों के शैक्षिक एवं सामाजिक सुधार करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। भारतीय संविधान में ऐसी परिकल्पना की गई है, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता पर आधारित है।

वर्तमान समय में इस समुदाय के लोगों ने उन सभी विकास की प्रक्रियाओं को अपनाया है जो सम्भवतः उनके विकास में सहायक सिद्ध हुई है। जनपद– हापुड़ भी विकास की इस लहर से अछूता नहीं रहा है। जनपद– हापुड़ के विकास में अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई है। इस सम्बन्ध में जनपद हापुड़ की हापुड़ नगर पालिका के विकास में अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा क्या प्रयास किये हैं? प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक प्रयास है। यह शोध कार्य जनपद हापुड़ की हापुड़ नगर पालिका का शोध कार्य है, जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों के द्वारा सामाजिक एवं राजनीतिक विकास की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। इस शोध कार्य का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के लोगों का जनपद–हापुड़ की हापुड़ नगरपालिका के सामाजिक विकास के कार्यों में उनके योगदान एवं उनकी भूमिका का उल्लेख है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि उनकी भूमिका, नेतृत्व की दृष्टि से क्या रही? और जनसाधारण की दृष्टि से क्या है?

अर्थ और परिभाषा

विकास– विकास का अर्थ ही व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना है। विकास एक प्रक्रिया है। अपेक्षित या वांछित दिशा में नियोजित परिवर्तन ही विकास है। विकास का शाब्दिक अर्थ है ''एक क्रमिक उन्मूलन, वृद्धि का प्रकट होना।''

हॉबहाउस के अनुसार– किसी भी समुदाय को तब विकसित कहा जाना चाहिए जब उसकी मात्रा, कार्यक्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की पारस्परिकता में वृद्धि होती है।

स्कॉफ के अनुसार– ''माप के पैमाने और संदर्भ के एक निश्चित प्रकार के परिवर्तनों को बताने वाला शब्द विकास है जो मूल्यों की एक निश्चित व्यवस्था के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से एक घटना की परिणामात्मक वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता हैं।''

डॉ0 योगेन्द्र सिंह के अनुसार– विकास को नियोजित सामाजिक परिवर्तन की एक रणनीति माना है। यह परिवर्तन उस दिशा में लाया जाता है जिसे समाज के सदस्य वांछित मानते हैं।

गुन्नार मिर्डल– विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था में उन वांछनीय अवस्थाओं का सुधार करना है जिनके कारण अल्प विकास की स्थिति बनी हुई है।

सामाजिक विकास

सामाजिक विकास के उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रों के साथ बदलते रहते हैं लेकिन इस विभिन्नता के होते हुए भी सामाजिक विकास का उद्देश्य मनुष्य जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में होता है।

गाल्टन के अनुसार– विकास का सिद्धान्त सामाजिक विज्ञानों का वह क्षेत्र है जहाँ अतीत का अध्ययन किया जाता है, वर्तमान की व्याख्या की जाती है और भविष्य का विश्लेषण किया जाता है। इस भाँति विकास के अन्तर्गत इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र और भविष्य विज्ञान आ जाते हैं।

एस0बी0 दुबे– सामाजिक विकास का तात्पर्य केवल आर्थिक विकास से न होकर जनकल्याण के विकास से भी होना चाहिए।

राजनीतिक विकास

आल्मण्ड और पावेल के अनुसार– राजनीतिक विकास राजनीतिक व्यवस्था के इनपुट के विशेष सन्दर्भ को विशेषीकरण के सार्थक परिवर्तन द्वारा गतिशीलता प्रदान करता है। परिवर्तन की सार्थकता के कोण में गिरावट आने से विकास की प्रकृति निशेधात्मक हो जाती है। राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ता हुआ लौकिकीकरण है।

रजनी कोठारी– राजनीतिक विकास 1950 में अस्तित्व में आये राष्ट्र राज्यों द्वारा अपने आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शक्ति और संसाधनों के निवेश का नाम है। इसके निर्गत रूप में राजनीतिक विकास भी संकल्पना बनी जिसके पीछे संगठित मानवीय चेतना विद्यमान थी। ''राजनीतिक विकास की समस्या वस्तुतः राजनीतिक संस्कृति, अधिनायकवादी संरचना तथा सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच सार्थक सम्बन्ध है।''

निष्कर्ष

अनुसूचित जाति की भूमिका नेतृत्व की दृष्टि में– नेतृत्व की दृष्टि से सामाजिक एवं राजनीतिक विकास में अनुसूचित जाति वर्ग की भूमिका के विषय में जानकारी एकत्र करने का प्रयास

किया गया है। हमारे द्वारा साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से जनपद–हापुड़ के विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध 100 जन–नेताओं से यह जानकारी एकत्र की गई–

उत्तरदाताओं की आयुगत संरचना

क्रमांक	आयु वर्ग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	30–40	20	20
2	41–50	50	50
3	50 से अधिक	30	30
		100	**100**

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध एक सौ जन नेताओं का 80 प्रतिशत चालीस वर्ष से अधिक उम्र का परिपक्व नेतृत्व प्रतीत होता है। जबकि 20 प्रतिशत नेताओं की उम्र 30–40 वर्श है।

उत्तरदाताओं की लिंग सम्बन्धी संरचना के सम्बन्ध में विभिन्न राजनीतिक दलों से सम्बद्ध एक सौ जन नेताओं में पुरुषों की भागीदारी 70 प्रतिशत तथा महिलाओं की भागीदारी 30 प्रतिशत है।

उत्तरदाताओं की जातिगत संरचना के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि सर्वाधिक प्रतिशत 65 प्रतिशत उच्च जाति का, 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति का तथा 15 प्रतिशत पिछड़ी जातियों का है। इससे स्पष्ट है कि आरक्षण के बावजूद भी पिछड़ी व अनुसूचित जातियों का नेतृत्व में आगमन प्रभावी नहीं हो पा रहा है।

उत्तरदाताओं की धार्मिक सरंचना के बारे में यह कहा जा सकता है कि धार्मिक रूप से इनका 70 प्रतिशत हिन्दू और शेष 30 प्रतिशत मुस्लिम है।

उत्तरदाताओं के व्यवसाय सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य में उत्तरदाताओं का 50 प्रतिशत व्यापार से सम्बन्धित है, 30 प्रतिशत नौकरी से सम्बन्धित है एवं 20 प्रतिशत घरेलू कार्य करते हैं। जो नेतृत्व में अपनी सहभागिता निभाते हैं।

उत्तरदाताओं की शिक्षा सम्बन्धी संरचना में व्यक्तिगत उत्तरों से स्पष्ट है कि केवल 10 प्रतिशत नेतृत्व अशिक्षित है तथा प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्राप्त नेतृत्व का प्रतिशत लगभग 70 है एवं शेष 20 प्रतिशत उच्च शिक्षा प्राप्त नेतृत्व है। यह भी स्पष्ट है कि उच्च स्तर के व्यक्ति सामान्य शिक्षा के उच्च एवं मध्यम जातियों के प्रति हिन्दू मतावलम्बी जन नेतृत्व से अधिक सक्रिय हैं।

राजनीतिक कार्यों में रुचि रखने वालों की तालिका से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 50 प्रतिशत नेतृत्व पिछले 20 वर्षों से, 30 प्रतिशत पिछले 30 वर्षों से तथा मात्र 20 प्रतिशत पिछले 10 वर्षों से राजनीतिक कार्यों में रुचि ले रहे हैं।

उत्तरदाताओं की राजनीतिक दल से सम्बद्धता के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं का 30 प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी, 30 प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी, 10 प्रतिशत कांग्रेस पार्टी, 10 प्रतिशत समाजवादी पार्टी, 05 प्रतिशत लोकदल से सम्बन्धित है।

उत्तरदाताओं के पूर्व में किसी दल की सदस्यता सम्बन्धी विवरण से स्पष्ट है कि मात्र 30 प्रतिशत जननेता ही पूर्व में किसी दूसरे दल से सम्बद्ध थे। इनमें अधिकांश भाग बहुजन समाज पार्टी

के जन नेताओं का था जो कि पूर्व में कांग्रेस (ई) से सम्बन्ध रखते थे तथा यह प्रतिशत सबसे कम अन्य दल का था लगभग (3.33 प्रतिशत) जो कि पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से सम्बन्धित था।

दल में प्राप्त पद सम्बन्धी संरचना के अनुसार 60 प्रतिशत उत्तरदाता राजनीतिक दलों में पदासीन नहीं हैं तथा शेष 40 प्रतिशत जन नेता पद पर आसीन हैं। इसके बावजूद यह स्पष्ट है कि वे राजनीतिक रूप से जागरुक हैं।

राजनीतिक संचरण के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि जनता की समस्याओं को राजनीतिक दलों में 40 प्रतिशत राजनीतिक रूप से सामने रख पाने में सक्षम रहे हैं और इस प्रक्रिया में सभाओं एवं समाचार पत्रों के द्वारा 30 प्रतिशत ने इन माध्यमों द्वारा समस्या को प्रस्तुत किया है। धरना प्रदर्शन में 16 प्रतिशत व जुलूस में 14 प्रतिशत बन्द के आयोजन एवं अन्य माध्यम हैं। विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संचरण के नकारात्मक एवं अवरोधी माध्यम यथा– धरना, जुलूस आदि जनसाधारण में कम प्रभाव रखते हैं अपेक्षाकृत सकारात्मक माध्यमों के जिसमें समाचार पत्र व राजनीतिक दल माध्यम हैं।

अनुसूचित जाति के लोगों को जाग्रत करने के सम्बन्ध में अधिकांश उत्तरदाताओं ने यह स्वीकारा है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लोगों को जाग्रत करने सम्बन्धी काफी प्रयास किये हैं। इस बात को स्वीकार करने वाले जन नेताओं का प्रतिशत 85 है। जबकि 15 प्रतिशत लोगों ने इसको अस्वीकार किया है।

संगठन में प्राप्त सदस्यता के सम्बन्ध में 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यह स्वीकार किया कि वे अनूसूचित जाति से सम्बन्धित किसी संगठन के सदस्य हैं जबकि 34 प्रतिशत किसी भी संगठन की सदस्यता से सम्बन्धित नहीं हैं।

निश्चित रूप से हित सामूहीकरण में नेतृत्व की भूमिका राजनीतिक दलों के द्वारा संगठन निर्मित करके ही की जाती है। 79 प्रतिशत नेतृत्व ने स्वीकार किया है कि उन्होंने स्थानीय समुदाय में संगठन निर्मित किये। दूसरे में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने में राजनीतिक नेतृत्व ने स्थानीय समुदाय में अहम भूमिका निर्वाहित की है। जबकि 21 प्रतिशत लोगों ने इस कार्य में कोई मदद नहीं की है।

विगत वर्षों में मतदान में भागीदारी के सम्बन्ध में उत्तरदाताओं में 72 प्रतिशत का यह मानना है कि अनुसूचित जाति के चुनाव में भागीदारी 72 प्रतिशत जबकि 28 प्रतिशत ने मतदान में कोई रुचि नहीं ली।

मत व्यवहार के लिए प्रोत्साहन के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं का सर्वाधिक योगदान 67 प्रतिशत लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना है, जबकि 33 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्होंने इस कार्य में कोई भूमिका नहीं निभाई है।

राजनीतिक जागरूकता में दलीय नेताओं की भूमिका के सम्बन्ध में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं का कहना है कि उन्होंने लोगों को राजनीतिक रूप से जाग्रत किया है जबकि 35 प्रतिशत लोगों ने इस कार्य में कोई रुचि नहीं ली है।

विकास के क्षेत्र में अनुसूचित जाति की भूमिका के सम्बन्ध में 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विचार है कि उन्होंने जनपद– हापुड़ के अनुसूचित जाति के लोगों के विकास में योगदान किया है, जबकि 17 प्रतिशत लोगों का विचार है कि उन्होंने अपनी भूमिका विकास के योगदान में नहीं निभाई है।

जनपद– हापुड़ के विकास में अनुसूचित जाति के लोगों के सम्बन्ध में स्पष्ट है कि 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से 38 प्रतिशत लोगों ने कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया, 17 प्रतिशत लोगों ने शहरी क्षेत्र में, 13 प्रतिशत लोगों ने ग्रामीण विकास में, 12 प्रतिशत लोगों ने कृषि के विकास में, 11 प्रतिशत लोगों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में तथा 9 प्रतिशत लोगों ने व्यापार के विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि अधिकतम 38 प्रतिशत लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में तथा न्यूनतम 9 प्रतिशत लोगों ने व्यापार के विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजनीतिक सहभागिता में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व गत दशक में तीव्रता से बढ़ा है। जिनमें जारुकता बढ़ी है और साथ ही उनके प्रति उच्च वर्ग का दृष्टिकोण प्रदर्शित–प्रवर्तित हुआ है जो कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था के स्थायित्व और समाज के एकीकरण की दिशा में सकारात्मक होता है।

संदर्भ

1. आलमण्ड, जी०ए०., पावेल, जी०बी०. (1978). ''कम्पूरिटिव पॉलिटिक्स– डेवलपमेन्ट एप्रोज बोरटन सीरीज. एमरिंद पब्लिशिंगः दिल्ली।
2. आहूजा, डॉ० राम. (1997). सामाजिक समस्याएँ और सामाजिक परिवर्तन. राजस्थान विश्वविद्यालयः जयपुर।
3. अग्रवाल, जी०के०., जैन, डॉ० जे०डी०. (1960). भारतीय संस्कृति एवं सामाजिक संस्थाएँ. साहित्य भवनः आगरा।
4. अम्बेडकर, डॉ० बी०आर०. (1974). द अनटचेबल्स. अमृत बुक कम्पनीः नई दिल्ली।
5. कोठारी, डॉ० रजनी. (1972). भारत में राजनीति. अनुवादक अशोक ओरिएन्ट लॉगमेंन लिमिटेडः नई दिल्ली।
6. कोठारी, डॉ० रजनी. (1988). भारत में राजनीति. संगम प्रेस लिमिटेडः पूना।
7. घुर्ये, जी०एस०. (1950). भारत में जाति एवं वर्ग. पॉपुलर बुक डिपोः बम्बई।
8. घुर्ये, जी०एस०. (1961). जाति वर्ग एवं व्यवसाय. पॉपुलर बुक डिपो. बम्बई।
9. दुबे, श्यामचरण. (2001). भारतीय समाज. नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डियाः नई दिल्ली।
10. दुबे, श्यामचरण. (1985). एक भारतीय ग्राम. नेशनल पब्लिशिंग हाउसः दिल्ली।
11. सिंह, योगेन्द्र. (1973). मार्डनाइजेशन ऑफ इण्डियन ट्रेडिशन. थाम्पसन प्रेसः फरीदाबाद।
12. हटिंग्टन. पॉलिटिकल डेवलपमेन्ट एण्ड पॉलिटिक डिके आलमण्ड पावे पूर्वारवत।